खण्ड-13, अंक-1, वर्ष-2025, मु0प्र0 149-155
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v13i1.27
SJIF (2025) : 8.749

Educational Status, Challenges, and Empowerment of Tribal Women in India

Abha Sharma
Department of Education, Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology, and Sciences
Prayagraj-211 001, U.P., India
abha43866@gmail.com

Submitted: 28-10-2025, Accepted: 27-11-2025

Abstract- The educational condition of tribal women in India has been a complex and long-standing challenge. This research paper presents a comprehensive and analytical study on this crucial issue. To gain a deeper understanding of the subject, we conducted an in-depth analysis of various government reports, census data, previous research studies, and policy documents. Our study reveals an alarming reality: despite several constitutional provisions and government schemes, the literacy rate among tribal women remains significantly low. This rate is not only much lower than the national average and that of the general female population, but also lags far behind tribal men. The research highlights the interlinked barriers—social, cultural, and economic—that restrict tribal girls from accessing education. These obstacles operate at multiple levels: Social and cultural factors, Economic constraints, Educational barriers. In this paper, we have also critically evaluated key government initiatives such as the *Midday Meal Scheme*, *Residential Schools*, and various *Scholarship Programs*. Our findings indicate a significant gap between policy intentions and ground-level implementation. Ultimately, this research emphasizes that education is not merely the acquisition of academic knowledge—it is a powerful tool for the economic, social, political, and psychological empowerment of tribal women. The paper urges for a holistic, inclusive, and culturally sensitive educational policy that addresses the real needs of tribal girls. We must strive to create a socio-economic environment that values education and ensures that tribal girls remain connected to the educational system rather than being left behind.

Key words- Tribal women, education, literacy rate, women empowerment, government policies, socio-economic barriers, motivation, dropout rate

भारत में आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, चुनौतियाँ और सशक्तिकरण

आभा शर्मा
शिक्षा शास्त्र विभाग, सैम हिगिंबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस
प्रयागराज–211 001, उ0प्र0, भारत
abha43866@gmail.com

सार– भारत में आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही चुनौती है। यह शोध पत्र इसी महत्वपूर्ण मुद्दे का एक व्यापक और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हमने इस विषय को गहराई से समझने के लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना के आँकड़ों, अकादमिक शोध और नीतिगत दस्तावेजों जैसे मौजूदा स्रोतों का गहन विश्लेषण किया है। हमारा अध्ययन एक चिंताजनक सच्चाई को उजागर करता है– तमाम संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर निराशाजनक रूप से कम बनी हुई है। यह दर न केवल राष्ट्रीय औसत और सामान्य महिला आबादी से, बल्कि आदिवासी पुरुषों की तुलना में भी काफी पीछे है।यह शोध उन जटिल और एक–दूसरे से जुड़ी बाधाओं की पड़ताल करता है जो आदिवासी लड़कियों को शिक्षा से दूर रखती हैं। इन बाधाओं को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं– सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक ढाँचागत शैक्षणिक। इस पत्र में, हमने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं जैसी प्रमुख सरकारी पहलों का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। हमने पाया कि अक्सर नीतियों के नेक इरादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है। अंततः, यह शोध इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, यह आदिवासी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण व आत्मनिर्भरता की कुंजी है। यह पत्र केवल अधिक स्कूल बनाने से आगे बढ़कर एक समग्र, एकीकृत और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नीति अपनाने की वकालत करता है। हमें एक ऐसा सामाजिक–आर्थिक माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो शिक्षा की माँग पैदा करे और आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में बनाए रखने में मदद करे।

बीज शब्द– आदिवासी महिला, शिक्षा, साक्षरता दर, महिला सशक्तिकरण, सरकारी नीतियां, सामाजिक–आर्थिक बाधाएं, आत्मनिर्भरता, सकल नामांकन अनुपात, स्कूल छोड़ने की दर

वैज्ञानिक ज्ञानवर्धक आलेख

1. **परिचय–** भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes – ST) एक महत्वपूर्ण समूह हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का लगभग 8–6 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। ये समुदाय प्रायः ग्रामीण, वनांचल और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। इस समुदाय के भीतर आदिवासी महिलाएँ सबसे अधिक असुरक्षित वर्गों में से एक मानी जाती हैं। वे "दोहरी असमानता" का अनुभव करती हैं–एक ओर जातीय पहचान के कारण सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना, तथा दूसरी ओर लैंगिक असमानता जो उनके अपने समुदाय और बाहरी समाज दोनों में व्याप्त है। उनका सामाजिक–आर्थिक जीवन अत्यधिक गरीबी, पोषणहीनता, अस्वस्थ जीवन परिस्थितियों और सीमित आजीविका विकल्पों से प्रभावित है। वे पुरुषों की तुलना में अधिक परिश्रम करती हैं और पारिवारिक आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, किंतु संसाधनों, संपत्ति और निर्णय–निर्धारण पर उनका नियंत्रण नगण्य रहता है। मेहनत के बावजूद उन्हें कम वेतन और सम्मान मिलता है, जिससे उनका श्रम अक्सर अदृश्य और अवमूल्यित रह जाता है। यही स्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है, जिसके परिणामस्वरूप वे वंचना और शोषण के एक अंतहीन चक्र में फँसी रहती हैं।

2. **सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा का महत्व–** शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, समानता और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में, शिक्षा केवल साक्षरता का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक चेतना का आधार है। यह उन्हें आत्मविश्वास, ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर जीवन के विविध निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि समुदाय के सामाजिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी ऊपर उठाती है। शिक्षा का प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है–एक शिक्षित माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के प्रति अधिक सजग रहती है, जिससे गरीबी और अशिक्षा का चक्र टूटने लगता है। इसलिए आदिवासी महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि संपूर्ण समुदाय के सतत विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

3. **शोध की समस्या–** भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने आदिवासी समुदायों की शैक्षिक स्थिति सुधारने हेतु अनेक योजनाएँ लागू कीं। इसके बावजूद, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर आज भी न केवल राष्ट्रीय औसत से, बल्कि आदिवासी पुरुषों की तुलना में भी कम बनी हुई है। यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में गहरे लैंगिक एवं सामाजिक विभाजन को उजागर करती है। मुख्य शोध समस्या यह है कि इतने वर्षों के प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद यह शैक्षिक असमानता क्यों बनी हुई है। यह समस्या केवल विद्यालयों तक पहुँच या संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं के जटिल तंत्र से जुड़ी है। आदिवासी बालिकाएँ अपनी शैक्षिक यात्रा के हर चरण में– नामांकन से लेकर शिक्षा पूर्ण करने तक–अनेक अवरोधों का सामना करती हैं। उच्च ड्रॉपआउट दर यह संकेत देती है कि केवल नामांकन पर्याप्त नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली में निरंतरता और अनुकूल वातावरण का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है।

4. **शोध के उद्देश्य**

1.भारत में आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति की समग्र समीक्षा करना

2.उन प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत बाधाओं को समझना जो आदिवासी महिलाओं की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

3.आदिवासी महिला शिक्षा से संबंधित सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

4.शिक्षा के माध्यम से आदिवासी महिलाओं में सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता में आने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

5. **शोध विधि–** यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसका उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों के आधार पर भारत में आदिवासी महिलाओं की शिक्षा, चुनौतियों और सशक्तिकरण की स्थिति का समग्र विश्लेषण करना है। अध्ययन किसी प्राथमिक डेटा पर आधारित नहीं है– इसमें उपलब्ध रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों, शोध लेखों और नीतिगत दस्तावेजों का संश्लेषण व विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

6. **संबंधित साहित्य सर्वेक्षण–** नैर, 2020 के अध्ययन "ट्राइबल वूमन ऐंड एजुकेशन इन इंडिया: इश्यूज ऐंड चौलेंजेज" में भारत के आदिवासी समुदायों में महिला शिक्षा की स्थिति और उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। शोध में पाया गया कि सामाजिक परंपराएँ, आर्थिक विषमताएँ और शिक्षा के प्रति सीमित जागरूकता, महिला शिक्षा के विकास में मुख्य बाधक हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि यदि शिक्षा नीतियों में सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई जाएँ, तो आदिवासी महिलाओं की साक्षरता में

उल्लेखनीय सुधार संभव है।[1] चौधरी 2019 ने अपने शोध "एजुकेशनल डेवलपमेंट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया–ए स्टडी ऑफ डिस्पैरिटीज" में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में साक्षरता दर में सुधार हुआ है, परंतु महिला साक्षरता अब भी अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है।[2]

राव और सिंह 2017 के शोध "एम्पॉवरिंग ट्राइबल वूमन थ्रू एजुकेशन: ए सोशिया–इकॉनॉमिक एनालिसिस" में शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन बताया गया है। लेखकों ने यह प्रतिपादित किया कि शिक्षा न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है।[3] शर्मा 2018 के अध्ययन "जेंडर ऐंड ट्राइबल एजुकेशन इन इंडिया: बैरियर्स ऐंड ऑपर्च्यूनिटीज" में यह बताया गया है कि आदिवासी समाजों में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा प्रणाली को इन सांस्कृतिक संदर्भों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि लिंग आधारित असमानताओं को कम किया जा सके।[4] भारत सरकार के योजना आयोग 2014 द्वारा प्रकाशित "इवैल्यूएशन स्टडी ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स" रिपोर्ट में आदिवासी शिक्षा विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अनेक योजनाएँ अपने लक्ष्यों तक सीमित रूप से पहुँच पा रही हैं, और वास्तविक लाभार्थियों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। रिपोर्ट में नीति–स्तर पर अधिक समन्वय और स्थानीय सहभागिता की अनुशंसा की गई है।[5]

7. डाटा संग्रह– इस अध्ययन के लिए डाटा विश्वसनीय द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किया गया है। प्रमुख स्रोतों में भारत सरकार की जनगणना रिपोर्टें (2001, 2011), पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यू.डी.आई.एस.ई. रिपोर्टें, तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े शामिल हैं। इसके साथ ही, आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित शैक्षणिक शोध पत्रों, सरकारी नीतिगत दस्तावेजों, वार्षिक रिपोर्टों और नीति आयोग व संसदीय समितियों की मूल्यांकन रिपोर्टों का भी विश्लेषण किया गया है।[6]

8. साक्षरता दर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य– साक्षरता किसी भी समाज के विकास का मूल संकेतक मानी जाती है। आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में यद्यपि साक्षरता दर में निरंतर सुधार हुआ है, फिर भी यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी और असमान रही है। 1961 में आदिवासी साक्षरता दर मात्र 8.53% थी, जो 2001 में बढ़कर 47.10% और 2011 में 59% तक पहुँची। परंतु जब लिंग के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, तो गहरा अंतर दिखाई देता है। 2001 में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर केवल 25.5% थी, जबकि आदिवासी पुरुषों की 48.2%। 2011 तक यह बढ़कर क्रमशः 49.4% और 68.5% हो गई – अर्थात् लगभग 20 प्रतिशत अंकों का लैंगिक अंतर अब भी बना रहा। यह अंतर सामान्य महिला आबादी की तुलना में और भी स्पष्ट होता है, क्योंकि 2011 में देश की कुल महिला साक्षरता दर 64.46% थी। इसका अर्थ है कि आदिवासी महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में "दोहरे नुकसान" का सामना कर रही हैं– एक अपने समुदाय के पुरुषों की तुलना में, और दूसरा सामान्य समाज की महिलाओं की तुलना में। राज्यवार तुलना भी व्यापक असमानता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, 2011 में हिमाचल प्रदेश में आदिवासी महिला साक्षरता दर 65.4% थी, जबकि राजस्थान (2001 में 42.2%) और आंध्र प्रदेश (40.9%) जैसे राज्यों में यह काफी कम थी। यह स्थिति दर्शाती है कि राष्ट्रीय औसत क्षेत्रीय विविधताओं को छुपा देता है और स्थानीय स्तर पर असमानताएँ अब भी गहरी हैं।[7]

9. स्कूल छोड़ने की दर एक गंभीर चिंता– आदिवासी बालिकाओं के सामने सबसे गंभीर शैक्षिक चुनौतियों में से एक है उच्च ड्रॉपआउट दर। यद्यपि साक्षरता और नामांकन दर में सुधार हुआ है, फिर भी बड़ी संख्या में लड़कियाँ प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुँचने से पहले ही शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली लगभग 24.82% आदिवासी बालिकाएँ कक्षा पाँच तक नहीं पहुँच पातीं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह दर बढ़कर 50.76% तक हो जाती है। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था में "लीकी पाइपलाइन" की समस्या को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।[8] सरकारी योजनाएँ और नामांकन अभियान जहाँ लड़कियों को स्कूल तक लाने में सफल हुए हैं, वहीं उन्हें विद्यालय में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसका कारण केवल पहुँच की कमी नहीं, बल्कि प्रतिधारण (Retention) और शिक्षा की गुणवत्ता (Quality) से जुड़ी प्रणालीगत कमजोरियाँ हैं। परिणामस्वरूप, शिक्षा पर किया गया प्रारंभिक निवेश निष्फल हो जाता है और अनेक बालिकाएँ पुनः गरीबी और वंचना के उसी दुष्चक्र में फँस जाती हैं, जिससे निकलने का साधन शिक्षा स्वयं है। शिक्षा की राह में बाधाएँ एक बहुआयामी विवेचना आदिवासी महिलाओं की निम्न शैक्षिक स्थिति के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि यह सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, अवसंरचनात्मक और शैक्षणिक बाधाओं के परस्पर जुड़े तंत्र का परिणाम है। ये कारक एक–दूसरे को मजबूत करते हुए एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है।

10. सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ लैंगिक भेदभाव– अनेक आदिवासी समुदायों में पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ अब भी प्रबल हैं, जहाँ लड़कों की शिक्षा को लड़कियों पर प्राथमिकता दी जाती है। बालिकाओं को प्रायः घरेलू कार्य, छोटे भाई–बहनों की देखभाल और कृषि श्रम में

संलग्न रहना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा को गैर–जरूरी व्यय के रूप में देखा जाता है।

11. बाल विवाह– कम उम्र में विवाह आदिवासी लड़कियों की शिक्षा में प्रत्यक्ष और गंभीर बाधा है। विवाह के बाद उनसे घरेलू और पारिवारिक दायित्व निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा अचानक समाप्त हो जाती है और उनके स्वास्थ्य व विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

12. सांस्कृतिक प्रतिरोध और परंपरागत मानसिकता– कुछ आदिवासी समुदाय औपचारिक शिक्षा को अपनी भाषा, संस्कृति और पारंपरिक पहचान के लिए खतरा मानते हैं। बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों के भय से वे औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा पारंपरिक ज्ञान और कौशल को अधिक महत्व देते हैं, जिससे विशेषकर महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

13. आदिवासी महिलाओं की शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ– आर्थिक विवशताएँ– आदिवासी समुदायों में व्याप्त गहरी गरीबी शिक्षा की सबसे बड़ी रुकावट है। परिवारों के लिए यूनिफॉर्म, किताबें और आने–जाने का खर्च उठाना कठिन होता है। कई बार बेटियों को स्कूल भेजने का अर्थ होता है घर के काम या श्रम में एक सहयोगी का अभाव, इसलिए माता–पिता शिक्षा के बजाय उन्हें काम में लगाना उचित समझते हैं। इस तरह की आर्थिक मजबूरियाँ लड़कियों के स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण बनती हैं।

14. भौगोलिक और अवसंरचनात्मक कठिनाइयाँ– अधिकांश आदिवासी बस्तियाँ दुर्गम और दूरदराज इलाकों में हैं जहाँ स्कूलों तक पहुँचना कठिन है। परिवहन सुविधाओं की कमी और असुरक्षित मार्ग लड़कियों के लिए शिक्षा को और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वहीं, कई स्कूलों में भवन, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल और विशेषकर लड़कियों के लिए अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं, जिससे उनकी उपस्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है।

15. शैक्षणिक एवं प्रणालीगत चुनौतियाँ– भाषा की बाधा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में शिक्षण माध्यम स्थानीय आदिवासी भाषाओं से भिन्न होता है। इससे छात्राएँ पाठ को ठीक से समझ नहीं पातीं और धीरे–धीरे शिक्षा से उनका लगाव कम हो जाता है। साथ ही, पाठ्यक्रम में आदिवासी जीवन या संस्कृति का प्रतिबिंब न होने से उन्हें शिक्षा अप्रासंगिक लगती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उनकी अनुपस्थिति से यह स्थिति और जटिल हो जाती है।[9] इन सभी कारकों की परस्पर जुड़ी प्रकृति बताती है कि केवल एक पहल पर्याप्त नहीं होगी। शिक्षा को सुलभ, प्रासंगिक और समावेशी बनाने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को एक साथ संबोधित करे।

16. सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ– भारत में आदिवासी छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएँ चलाई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना, आर्थिक सहयोग देना और स्कूल छोड़ने की दर को घटाना है।[10]

17. मुख्य योजनाएँ– सबसे उल्लेखनीय योजना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिनमें 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह आश्रम स्कूल दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे भौगोलिक या आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहें। छात्रवृत्ति योजनाएँ भी इस दिशा में अहम भूमिका निभाती हैं।

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति से कक्षा 9–10 के छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकें।

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है।

वहीं, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी योजनाएँ योग्य आदिवासी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर देती हैं, जिनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

बालिकाओं के लिए विशेष रूप से कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की योजना चलाई गई है

जो गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से शैक्षिक परिसर स्थापित कर नामांकन और निरंतरता दोनों बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराती है।

18. योजनाओं का मूल्यांकन और सीमाएँ– इन योजनाओं की भावना सराहनीय है, परंतु उनके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। संसदीय समितियों और अन्य मूल्यांकन रिपोर्टों ने बताया है कि धन वितरण में देरी, राज्य सरकारों की उदासीनता और निगरानी की कमी जैसी समस्याएँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं। कई विद्यालयों में बुनियादी ढाँचे की कमी, योग्य शिक्षकों की अनुपस्थिति और भोजन की निम्न गुणवत्ता जैसी शिकायतें आम हैं। इसके अलावा, अनेक समुदायों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती। प्रचार–प्रसार और मार्गदर्शन की कमी के कारण वास्तविक लाभार्थी तक सहायता पहुँच ही नहीं पाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश योजनाएँ "आपूर्ति–पक्ष" यानी संसाधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं, जबकि "मांग–पक्ष" की चुनौतियाँ जैसे गरीबी, सामाजिक पूर्वाग्रह और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी अभी भी उपेक्षित हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा जब सरकार केवल ढाँचे और वित्त पर नहीं, बल्कि समुदाय के भीतर शिक्षा की आवश्यकता और मूल्य के प्रति विश्वास जगाने पर भी समान रूप से ध्यान दे।

19. शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता एक वैचारिक रूपरेखा– आदिवासी महिलाओं की शिक्षा के वास्तविक महत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के बीच के परस्पर संबंधों को स्पष्ट रूप से देखें। ये तीनों अवधारणाएँ एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं–शिक्षा सशक्तिकरण का आधार है, और सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम।[11] महिला सशक्तिकरण की अवधारणामहिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णयों पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाती है। यह केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, और राजनीतिक सभी स्तरों पर परिवर्तन की बात करती है।

20. आत्मनिर्भरता का वैचारिक मॉडल– आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल बाहरी सहायता से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यक जरूरतों को स्थायी और सम्मानजनक तरीके से पूरा करने की क्षमता विकसित करना है। इसे एक व्यक्ति, परिवार या समुदाय की सामाजिक और आर्थिक आत्मसंतुष्टि के रूप में देखा जा सकता है।

इस मॉडल में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं

1-बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता।

2-संसाधन इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन जैसे रोजगार, वित्तीय संसाधन और ऋण की पहुँच।

3-स्थिरता के संकेतक जैसे बचत, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक पूंजी और शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य, जो दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, शिक्षा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता दोनों की आधारशिला है। यह न केवल ज्ञान का माध्यम है, बल्कि उस चेतना का भी स्रोत है जो उन्हें अपने जीवन और समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान करती है।

21. **शिक्षा और सशक्तिकरण के बीच अंतर्संबंध–** शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नींव है। यह केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि वह उत्प्रेरक शक्ति है जो महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने और अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर देती है।[12] शिक्षा से महिलाओं में संज्ञानात्मक सशक्तिकरण आता है–वे अपने अधिकारों, अवसरों और सामाजिक असमानताओं को समझने लगती हैं। ज्ञान और कौशल प्राप्त करने से उनमें मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण विकसित होता है, जो आत्मविश्वास, आत्म–सम्मान और आत्मनिर्णय की भावना को सुदृढ़ करता है।इसके साथ ही शिक्षा महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। बेहतर रोजगार और आय के अवसर उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे वे संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अंततः, एक शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त महिला न केवल अपने परिवार में, बल्कि समाज और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। वह निर्णय लेने में सक्षम होती है और अपने समुदाय में परिवर्तन की वाहक बनती है। इस प्रकार, शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मबोध और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा है।

22. **शिक्षा का प्रभाव सामाजिक–** जब आदिवासी महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहता। यह उनके परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गहराई से बदल देता है।[13]

23. **आर्थिक सशक्तिकरण–** शिक्षा आदिवासी महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलने और बेहतर रोजगार या उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। इससे वे केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारती ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान देती हैं। वित्तीय साक्षरता के साथ वे अपनी आय का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, बचत कर सकती हैं और आर्थिक निर्णयों में आत्मविश्वास से भाग ले सकती हैं।

24. **सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण–** शिक्षा महिलाओं में अधिकारों की जागरूकता और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है। एक शिक्षित महिला बाल विवाह, दहेज या घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखती है। वह समुदाय में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है और सामूहिक परिवर्तन की दिशा में नेतृत्व करती है। राजनीतिक रूप से भी शिक्षित महिलाएँ अधिक भागीदारी करती हैं–मतदान से लेकर स्थानीय शासन में नेतृत्व तक। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का साधन नहीं, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति और लैंगिक समानता की दिशा में सबसे सशक्त औजार है।

25. **मनोवैज्ञानिक परिवर्तन–** शिक्षा का सबसे गहरा असर महिलाओं के मनोवैज्ञानिक विकास पर दिखाई देता है। यह आत्मविश्वास, आत्म–सम्मान और आत्म–प्रभावकारिता की भावना को मजबूत बनाती है। शिक्षित महिलाएँ अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करती हैं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं और उन्हें हासिल करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाती हैं। शिक्षा उन्हें सामाजिक सीमाओं और परंपरागत रूढ़ियों को चुनौती देने का साहस देती है, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य गढ़ पाती हैं।

26. **स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव–** शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। शिक्षित महिलाएँ स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को बेहतर समझती हैं। वे टीकाकरण, परिवार नियोजन और चिकित्सा सलाह को अपनाने में अधिक सक्रिय रहती हैं। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है और पूरे परिवार का स्वास्थ्य सुधरता है। शिक्षा आदिवासी महिलाओं में एक "गुणक प्रभाव" उत्पन्न करती है– वे न केवल अपना जीवन सुधारती हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश करती हैं। यह परिवर्तन गरीबी, अशिक्षा और अस्वास्थ्य के चक्र को तोड़ते हुए आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। इसलिए, आदिवासी महिला शिक्षा केवल सामाजिक सुधार का माध्यम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है जो पूरे समाज को सशक्त बनाती है।

27. **निष्कर्ष एवं सुझाव–** इस अध्ययन से स्पष्ट है कि आदिवासी महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में अब भी गहरी असमानताओं का सामना कर रही हैं। साक्षरता और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी सीमित है, और सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक व अवसंरचनात्मक बाधाएँ उनके मार्ग में प्रमुख रुकावट बनी हुई हैं। सरकारी योजनाएँ तो बनी हैं, पर उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर सीमित रहा है। फिर भी जहाँ भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिले हैं, वहाँ शिक्षा ने आदिवासी महिलाओं और उनके समुदायों में वास्तविक परिवर्तन लाया है–आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सभी स्तरों पर।

नीतिगत सुझाव

1-सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षाः पाठ्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को शामिल किया जाए ताकि बच्चे शिक्षा से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें।
2-बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ करें– आदिवासी क्षेत्रों के पास स्कूल, छात्रावास और सुरक्षित परिवहन की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
3-आर्थिक प्रोत्साहन– छात्रवृत्तियाँ और सशर्त नकद प्रोत्साहन (Conditional Cash Transfers) देकर परिवारों को लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए।
4-समुदाय की भागीदारी स्कूल प्रबंधन समितियों में आदिवासी महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए और स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
5-शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों को आदिवासी भाषा और संस्कृति की समझ दी जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील और प्रभावी शिक्षण दे सकें।
6-एकीकृत दृष्टिकोण शिक्षा नीतियों को स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार योजनाओं से जोड़कर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए।

References

1. Nair, P. (2020). *Tribal Women and Education in India: Issues and Challenges*. *Journal of Social Development Studies*, 15(2), 45–58.
2. Choudhury, A. (2019). *Educational Development among Scheduled Tribes in India: A Study of Disparities*. *Indian Journal of Human Development*, 13(1), 23–37.
3. Rao, N., & Singh, M. (2017). *Empowering Tribal Women through Education: A Socio-Economic Analysis*. *Indian Journal of Gender Studies*, 24(3), 412–428.
4. Sharma, P. (2018). *Gender and Tribal Education in India: Barriers and Opportunities*. *Social Change*, 48(2), 205–220.
5. Planning Commission of India. (2014). *Evaluation Study on Educational Development of Scheduled Tribes*. Government of India.
6. Ministry of Education. (2022). *Unified District Information System for Education Plus (UDISE+ 2021–22)*.

Government of India.
7. Government of India. (2011). *Census of India 2011: Primary Census Abstract for Scheduled Tribes*. Office of the Registrar General and Census Commissioner, New Delhi.
8. National Sample Survey Office (NSSO). (2022). *Education in India: NSS 76th Round (2018–19)*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
9. UNESCO. (2021). *State of the Education Report for India: No Teacher, No Class*. New Delhi: UNESCO.
10. Ministry of Tribal Affairs. (2023). *Annual Report 2022–23*. Government of India.
11. Rao, N., & Singh, M. (2017). *Empowering Tribal Women through Education: A Socio-Economic Analysis*. *Indian Journal of Gender Studies*, 24(3), 412–428.
12. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
13. Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. Princeton University Press.